ऑयल इंपोर्ट घटाने के लिए एथेनॉल प्रॉडक्शन बढ़ाने का प्लान

[ऋतुराज तिवारी। नई दिल्ली]

सरकार क्रूड ऑयल के आयात में कटौती करने के लिए एथेनॉल के प्रॉडक्शन में भारी इजाफा करने और पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वह अगले दो वर्षों में एथेनॉल के प्रॉडक्शन की मौजूदा 355 करोड़ लीटर की क्षमता को बढ़ाकर 900 करोड़ लीटर करने की योजना बना रही है। फूड मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया, 'सरकार ने 550 करोड़ लीटर की नई क्षमता स्थापित करने के लिए चीनी मिलों में 362 नए प्लांट शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।' कैपेसिटी बढ़ने से 2022 तक 10 पर्सेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग का सरकार का टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। इस कदम से सालाना 20 लाख टन तेल की जरूरत को घटाया जा सकेगा और ऑयल इंपोर्ट बिल 7,000 करोड़ रुपये तक कम हो जाएगा। एथेनॉल गन्ने की पेराई कर शीरा बनाए जाने के समय निकलने वाला बाई-प्रॉडक्ट है। इसे तीन तरीकों- सीधे गन्ने के रस से, बी-ग्रेड और सी-ग्रेड शीरे से बनाया जा सकता है।

सरकार ने अगले 2 सालों में एथेनॉल के प्रॉडक्शन की मौजूदा 355 करोड़ लीटर की क्षमता को बढ़ाकर 900 करोड़ लीटर करने की योजना बनाई है

गन्ने के रस से बने एथेनॉल की कीमत को 59.48 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। वहीं, सी-ग्रेड शीरे से निकले एथेनॉल का दाम 43.75 लीटर और बी-ग्रेड से निकले एथेनॉल की कीमत को 54.27 लीटर रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि 10 पर्सेंट ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करने के लिए देश में कम से कम 425 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, 'पिछले साल पेट्रोल के साथ 191 करोड़ लीटर एथेनॉल मिलाया गया था जो सिर्फ 5.5 पर्सेंट था। इस साल अब तक ऑयल कंपनियों ने 140 करोड़ लीटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा अतिरिक्त 31 करोड़ लीटर के कॉन्ट्रैक्ट पर अभी चर्चा चल रही है। ऑयल कंपनियों की ओर से 511 करोड़ लीटर की मांग है। चूंकि प्रॉडक्शन लगभग 21 पर्सेंट घटा है, इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट के 4.5 पर्सेंट के ही हासिल होने की संभावना है। सरकार शुगर कंपनियों की प्रॉफिटैबिलिटी बढ़ाना चाहती है। इसलिए अगले दो सालों में वह कम से कम 7-8 लाख टन सरप्लस शुगर को एथेनॉल प्रॉडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगी।

अधिकारी ने कहा, 'खराब मौसम के चलते इस साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन घटा है। अगर अगले सीजन में उत्पादन बढ़ता है तो दोगुनी मात्रा को एथेनॉल प्रॉडक्शन के लिए भेजा जा सकता है।' हालांकि, शुगर मिलों की माली हालत खस्ता होने से एथेनॉल प्रॉडक्शन की नई कैपेसिटी बढ़ाने का रास्ता आसान नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए 362 प्रस्ताव आए हैं। इनमें से बैंक अब तक सिर्फ 56 प्रोजेक्ट को कर्ज देने के लिए राजी हुए हैं। शुगर इंडस्ट्री की संस्था ISMA के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने कहा, 'सरकार को शुगर कंपनियों के एथेनॉल प्रॉडक्शन प्लांट के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए।'

Economic Times
4/1/20